सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 26 AUGUST TO 1 SEPTEMBER 2020 • VOLUME- 5 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

कांग्रेस की महाभारत अभी बाकी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं सामूहिक नेतृत्व की पैरवी करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।

उन्होंने ट्वीट किया, ''यह पद के लिए नहीं है। यह मेरे देश के लिए है, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है।'' गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने यह टिप्पणी उस वक्त की है कि जब एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी और फिर उन पर सिब्बल की तरफ से निशाना साधे जाने के

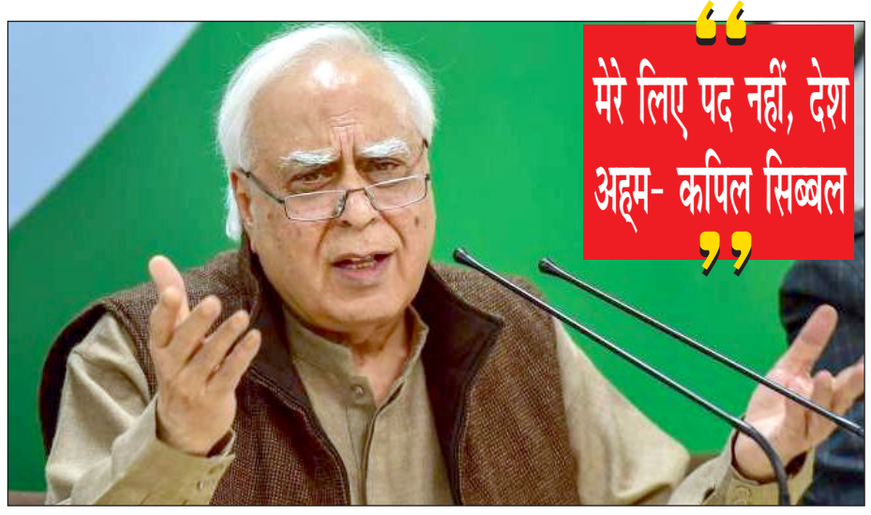

बाद विवाद हो गया था। बाद में सिब्बल ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें सूचित किया कि उनके हवाले से जो कहा गया है वो सही नहीं हैं और ऐसे में वह अपना पहले का ट्वीट वापस लेते हैं। सिब्बल ने ट्वीट किया, ''राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे सूचित किया कि उन्होंने वो कभी नहीं कहा था जो उनके हवाले से बताया गया है। ऐसे में मैं अपना पहले का ट्वीट वापस लेता हूं।''

इससे पहले सिब्बल ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी को लेकर उनपर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में भाजपा के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, इसके बावजूद 'हम भाजपा के साथ साठगांठ कर रहे हैं।'

खबरों में कहा गया था कि राहुल गांधी ने पत्र लिखने वाले नेताओं पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाया, हालांकि बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की।

सोनिया को पत्र लिखने वाले नेताओं ने कहा- कांग्रेस नेतृत्व को कभी नहीं दी चुनौती

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक एवं सक्रिय अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कई ने मंगलवार को कहा कि उन्हें विरोधी नहीं समझा जाए और उन्होंने कभी भी पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की हंगामेदार और मैराथन बैठक के एक दिन बाद इन नेताओं ने यह भी कहा कि पत्र लिखने का मकसद कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अविश्वास जताना नहीं था और वे सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के फैसले का स्वागत करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। वह भी इन 23 नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ''यह पद के लिए नहीं है। यह मेरे देश के लिए है, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है।'' गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने यह टिप्पणी उस वक्त की है कि जब एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी और फिर उन पर सिब्बल की तरफ से निशाना साधे जाने के बाद विवाद हो गया था। बाद में सिब्बल ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें सूचित किया कि उनके हवाले से जो कहा गया है वो सही नहीं हैं और ऐसे में वह अपना पहले का ट्वीट वापस लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पत्र लिखने वाले नेताओं का इरादा देश के मौजूदा माहौल को लेकर 'साझा चिंताओं' से नेतृत्व को अवगत कराना था और यह सब पार्टी के हित में किया गया। पार्टी सांसद विवेक तन्खा के एक ट्वीट के जवाब में शर्मा ने कहा, ''अच्छा कहा। पार्टी के हित में और देश के मौजूदा माहौल एवं संविधान के बुनियादी मूल्यों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया।''

पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल राज्यसभा सदस्य तन्खा ने ट्वीट किया, ''हम विरोधी नहीं हैं, बल्कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के पैरोकार हैं। यह पत्र नेतृत्व को चुनौती देना नहीं था, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कदम उठाने के लिए था। चाहे अदालत हो या फिर सार्वजनिक मामले हों, उनमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ कवच होता है। इतिहास बुजदिल को नहीं, बहादुर को स्वीकारता है।''

आवारा पशुओं की दयनीय हालत के लिए कौन जिम्मेवार

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

पंजाब के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आजकल किसी खतरनाक वीडियो गेम से कम नहीं है जिस प्रकार बच्चों की वीडियो गेम कार रेसिंग में गाड़ी चलाते समय अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आवारा पशु किसी चुनौती से कम नहीं है इसका उदहारण आपको फगवाड़ा रोपड़ हाईवे जिसको कितने सालों से लंबित चली आ रही मांग को भाजपा की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शुरू करवाया राजनीतिक पार्टियों के अनेकों मंत्री इस मार्ग से रोज़ाना गुज़रते है परन्तु किसी को इन आवारा पशुओं को देखकर तरस नहीं आता की इनको रोज़ वाहनों से टकराकर घायल होना पड़ रहा है और वाहनों में सवार कई मासूमों को अनचाही मृत्यु प्राप्त हो रही है इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है और हैरानी की बात यह है की पशुपालन मंत्री इस मार्ग से खुद चंडीगढ़ से अपने पैतृक गाओं में हर हफ्ते जाते है वो भी समाचार पत्रों या टीवी चैनलों में ब्यान देकर पल्ला झाड़ लेते है की हमने केंद्र को पत्र लिखा

फगवाड़ा रोपड़ हाईवे टोल से पहले आवारा पशुओं का जमावड़ा किसी हादसे को न्यौता देता हुआ। छाया : रवि

है की हमें गायों की पहचान बारे बताया जाये यह सब मात्र खानापूर्ति छोड़ कर इसके इलावा कुछ नहीं है जब टोल कंपनी के पेट्रोलिंग टीम से पूछो जिनकी जिम्मेवारी है रोड पर किसी भी आवारा पशुओं को ना आने देना परन्तु वो अपनी जिम्मेवारी पुलिस पर छोड़ देते है इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में पीस आम जनता रही है या आवारा पशु। जालंधर ब्रीज द्वारा पहले भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाईवे के ध्यान में अपने समाचार पत्र के माध्यम से जगाने का प्रयास किया और कल के मौजूदा हालातों की ग्राउंड जीरो की तस्वीरों को व्हाट्सप्प के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया अब देखना होगा इस पर वो क्या कार्यवाही करते है?

यू.पी. में पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या: योगी सरकार पर बरसीं प्रियंका गांधी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक पत्रकार की कथित हत्या को लेकर मंगलवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है और अपराध बढ़ता ही जा रहा है।

प्रियंका ने ट्वीट किया, '' 19 जून को शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई को विक्रम जोशी की हत्या और 24 अगस्त को रतन सिंह की हत्या....। उप्र में पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या। 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते प्राथमिकी दर्ज की गई।'' उन्होंने कहा कि उप

सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने आरोप लगाया, '' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम्। ये उप्र में केवल दो दिनों का अपराध का मीटर है।

सरकार बार-बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है।'' गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र में सोमवार रात्रि एक निजी हिंदी टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी गयी। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुडा का मंत्री बदलने से भी भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

लोकसभा 2019 के चुनावों में कांग्रेस को शहरी हलकों में भारी हार का सामना करना पड़ा था जिसके कारण मुख्यमंत्री पंजाब ने बढ़े स्तर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल किये थे जिसमें मुख्यतय निकाय विभाग और पुडा के विभाग के मंत्री को बदलना जिसमें मुख्यमंत्री ने एक तीर से दो निशाने लगाए जिसमें अपनी पार्टी के अंदर रहकर ही मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी मंचों से बोलना पूर्व निकाय मंत्री को महंगा पढ़ गया जिसके परिणाममस्वरुप आज उनका राजनीतिक भविष्य हाशिया पर चला गया पर इस कड़ी में मुख्यमंत्री के

खासमखास को कुर्बानी देनी पड़ी जिसमें उनको पंजाब के अहम विभाग खोकर एक तरह से मामूली विभाग लेकर ही संतुष्टि दिखानी पढ़ी परन्तु जिस खराबी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने फेरबदल किये उसका परिणाम ग्राउंड जीरो पर शुन्य है उसका मुख्य कारण विभाग जालंधर डिवल्वमैंट अर्थारिटी विभाग में दीमक की तरह बैठे पिछले कुछ सालों से एक ही कुर्सी पर बैठे भ्रष्ट अफसर है जो लोगों को आज भी अपनी गंदी आदतों से तंग परेशान कर रहे है और लोगों को सुविधा देने की बजाय दुविधा में डाल रहे है जो की कांग्रेस की सरकार के अक्स को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और सबसे बढ़े विभाग में किसी भी काबिल उच्चाधिकारी का ना होना जो इन पर नकेल डाल सके अगर यही हालात रहे तो 2022 में कांग्रेस को दिल्ली की तरह शुन्य पर ही सीमित रहना पढ़े।

सीबीआई कराने जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के मस्तिष्क का पोस्टमार्टम

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हेंडल कर रही है। पिछले दिनों सीबीआई सुशांत के बांद्रा वाले घर गयी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई हत्या

और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही हैं। सुशांत की मौत के दौरान घर में मौजूद लोगों से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की है। सुशांत मामले में एक बात और सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत राजपूत के मस्तिष्क का पोस्टमार्टम होगा। दिमाग का पोस्टमार्टम यानी मनोवैज्ञानिक शव परीक्षा जिसे जांच एक्सपर्ट की भाषा में साइकोलॉजी ऑटोप्सी कहते हैं।

बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा बिजली चोरी करने वालों के ऊपर लिया गया कड़ा एक्शन

''बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी करने वालों के अवैध कनेक्शन काटे गए''

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने गत दिनों बिजली चोरी की शिकायतें मिलने के संबंध में उप मुख्य इंजीनियर हरजिंदर सिंह बांसल जालंधर सर्कल की देख रेख में

छाया : रवि

पाँच अलग अलग जगह से टीमे गठित करके जालंधर और फगवाड़ा मंडल के अधीन आते इलाकों जिसमे पिछोरी मोहला, कांशी नगर ,मॉडल हाउस, बस्ती शेख, काला संघा रोड ,साई कॉलोनी ,ईश्वर कॉलोनी, रसूलपुर कलां, खुरला किंगरा, लांबड़ा ,रामपुर ललियाँ, कुराली ,उचा सुराज गंज, पारस एस्टेट ,नहालां कॉलोनी, शिव नगर, शिवा जी पार्क, विर्दी कॉलोनी, डभी मोहल्ला, न्यू रसीला नगर, प्रीतम नगर, भगतपुरा, शहीद उधम सिंह नगर, कोट रानी रामपुरा और रायपुर की चैकिंग की गयी।

इस दौरान कुल 1247 कनेक्शन चेक किये गए जिसमे बिजली चोरी और अलग अलग मामलो को देखते हुए कुल 15.28 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया और चोरी के मामलो में करदाताओं के ऊपर बिजली एक्ट 2003 के अंतर्गत सेक्शन 135 अधीन अलग अलग पुलिस डिवीज़न में मामला दर्ज भी करवाया जा रहा है ।

इतनी बड़ी रेड़ के बाद मुख्य इंजीनियर जैन इन्दर दानिया की तरफ से लोगो को अपील की गयी की अगर कोई बिजली चोरी का मामला किसी के ध्यान में आता है वह सीधा इसकी जानकारी 96461-16301 में कॉल करके दे और जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

दखल

आखिर कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार और लूट पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि हम असीमित उपभोग पर भी रोक लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि समाज में आर्थिक विषमता कम हो। अगर हम अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी तय करते हैं, तो किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी के एक दिन का अधिकतम पारिश्रमिक एक हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। संपत्ति और समृद्धि के भोंडे प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

यह चिंता का विषय है कि भ्रष्टाचार बौद्धिक बहस का हिस्सा बना रहता है, लेकिन चुनाव का मुद्दा बन नहीं पाता। कभी मुद्दा बना ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 74 का बिहार आंदोलन, जो बाद में इमरजेंसी के खिलाफ हो गया, छात्रावासों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही शुरू हुआ था। वीपी सिंह के नेतृत्व में हुए चुनाव का मुख्य मुद्दा राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ही था। लेकिन धीरे-धीरे यह चुनावी एजेंडे से बाहर चला गया। इसकी एक वजह संभवतः यह हुई कि अगड़ी राजनीति के खिलाफ पिछड़ी राजनीति का दौर शुरू हुआ और उसके जवाब में राम मंदिर आंदोलन और राजनीति के केंद्र में आ गया जातीय व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। अब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। बिहार में एक दर्जन से अधिक कुख्यात अपराधी विधायक बने, कुछ सांसद भी, क्योंकि उनका एक वोट बैंक था। जातीय समीकरणों से उभरे नायक दागी भी हों तो उनके मतदाताओं को उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वे मायावती हों, मुलायम हों, लालू हों या कोई और।

यह फेहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है। अहम बात यह कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी संवेदना लगातार भोथरी होती गई है। ईमानदारी को अब एक अनजान वस्तु, जुनून या फिर कोरा आदर्श माना जाने लगा है। ऊपरी कमाई सामाजिक स्टेटस। हम बेटी या बहन के लिए वर ढूंढने निकलते हैं तो कभी यह सवाल हमारे जेहन में नहीं उठता कि वर ईमानदार है या नहीं। उलटे ऊपरी कमाई की संभावना से बेटी का बाप आश्वस्त होता है, बेटी खाते-पीते घर में जा रही है। पहले किसी एक जगह फायरिंग होती थी तो पूरे देश में सिहरन दौड़ जाती थी, अब हर रोज हिंसक वारदातें! अब हम हिंसा, बलात्कार की घटनाओं की खबर चैनलों पर देखते हुए मजे से ब्रेड पर मक्खन लगा कर खाते रहते हैं। ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार को लेकर भी हमारी संवेदना कुंद हो चुकी है। भ्रष्टाचार चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अब उस चिंता में संजीदगी नजर नहीं आती। जो भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, उनके लिए भी भ्रष्टाचार कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं, क्योंकि अवसर मिलने पर वे खुद भी भ्रष्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनाक्रोश होना चाहिए, वह कहीं दिखाई नहीं देता।

भ्रष्टाचार सर्वव्यापी और सर्वग्रासी बनता जा रहा है और एक कृत्रिम किस्म की लड़ाई उसके खिलाफ जारी रहती है। कभी सूचना के अधिकार के रूप में, कभी लोकपाल विधेयक के रूप में। अगर भ्रष्टाचार से किसी को कोई खास शिकायत नहीं तो भ्रष्टाचार चलते रहने में क्या हर्ज है? हर्ज है। क्योंकि भ्रष्टाचार से व्यापक समुदाय का हित प्रभावित होता है, हम सबका भविष्य प्रभावित होता है। आखिरकार, हर तरह से साधन-संपन्न होने के बावजूद हमारे देश का शुमार दुनिया के सबसे पिछड़े-विपन्न देशों में क्यों होता है? ज्यादा भूखे, नंगे, कुपोषित और अनपढ़ लोग हमारे देश में क्यों हैं? अगर हममें थोड़ी-सी भी मानवीय चेतना है, अपने देश के लिए आत्म-गौरव का भाव है तो हमें इस सवाल से बेचैन होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपायों पर विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर काबू पाने का कोई मुकम्मल तरीका तो नजर नहीं आता, लेकिन इस दिशा में हम कुछ एहतियाती कदम तो उठा सकते हैं। लेकिन पहले इस बात को दिमाग से साफ कर लेना चाहिए कि कानून बना कर इस भ्रष्टाचार पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। क्या रिश्वत लेना और देना आज की तारीख में अपराध नहीं? दहेज के खिलाफ कानून नहीं? लेकिन रिश्वत बखूबी चल रहा है। दहेज अब भी लिया जाता है, दिया जाता है। पुलिस है, प्रशासन है, एक मोटा-सा लिखित संविधान है, कोर्ट-कचहरी है। तरह-तरह की जांच एजेंसियां हैं। फिर भी भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। अन्ना हजारे का मानना था कि अगर उनकी मांग के मुताबिक लोकपाल कानून बन गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।

लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा इस नई व्यवस्था में? हर शहर में कोर्ट-कचहरी के अलावा लोकपाल का भवन होगा। जो जांच एजेंसियां हैं, उन पर विश्वास नहीं, इसलिए हो सकता है लोकपाल के अलावा एक पूरी नई व्यवस्था हो। लेकिन इस व्यवस्था से जुड़े लोग हमारे इस भ्रष्ट समाज के बाहर के लोग होंगे? यह बहस फिर भी चलती रहती है। इससे यह उम्मीद बनती है कि अब भी इस व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश है। लेकिन नए उपायों के क्रियान्वित होने तक हम कुछ और बातों पर भी गौर कर सकते हैं, जो सामाजिक जीवन में चर्चा का विषय बनती रही हैं। इससे और कुछ हो या न हो, भ्रष्टाचार को रोकने का सवाल कुछ मूर्त हो सकता है। एक पुरानी कहावत है- सत्ता भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्णरूपेण भ्रष्ट बनाती है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। गांधी, लोहिया के चौखंभा राज व्यवस्था के सपने को सच्चे अर्थों में साकार कर हम सत्ता और धन का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। सत्ता में सामान्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर और सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाकर हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं।

हमने पंचायती व्यवस्था कायम तो कर रखी है, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं दी है। कार्यपालिका में दखल वह नहीं दे सकती। मसलन, प्रखंड कार्यालय का बीडीओ भ्रष्ट है, थानेदार क्रूर है तो पंचायत के जरिए उसे स्थानांतरित नहीं कर सकते, उसको सजा देने की सिफारिश भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बहते झरने की तरह। यह बात हर प्रबुद्ध व्यक्ति जानता-समझता है। झरने के तल को साफ कर हम झरने को शुद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए तो झरने के निकास स्थल से हमें सफाई अभियान शुरू करना होगा। अगर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार-मुक्त होगा तो वह नौकरशाही और नीचे के भ्रष्टाचार पर भी रोक लगा सकेगा। यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ कारगर नहीं हो सकती। इसलिए बड़े-बड़े भव्य मंचों से जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं, उन्हें और उनके करीब के लोगों को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त होना होगा।

कुछ लोगों की राय है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की सजा बहुत कम है। इसलिए भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति जरा भी डरता नहीं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दो-चार वर्ष की सजा हो भी गई तो क्या गम है? भारतीय दंड विधान में कोर्ट के पेशकार की सौ पचास रुपए की रिश्चत लेने की सजा और करोड़ों का घोटाला करने की सजा लगभग एक है। सरकार में बैठे लोगों के लिए तो सजा इतनी काफी समझी जाती है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन काफी नहीं। एक करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के लिए उम्रकैद की सजा होनी चाहिए। हम भ्रष्टाचार को अत्यंत सीमित अर्थ में ही लेते हैं। उसे भादवि की धाराओं से परिभाषित करने की हमारी आदत है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ वह नहीं, बहुत-सी बातें भ्रष्टाचार ही हैं, लेकिन कानूनी दायरे में नहीं आतीं।

उन्हें हम कानून-सम्मत भ्रष्टाचार कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब लाखों लोग मुंबई के फुटपाथों पर जीते हैं, तब जनप्रतिनिधियों का आलीशान बंगलों में रहना भ्रष्टाचार ही तो है। न्यूनतम मजदूरी हम 120 रुपए तय करते हैं तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना कानून सम्मत भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। इसलिए कानून की धाराओं के अनुसार जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन पर रोक तो जरूरी है ही, कानूनसम्मत भ्रष्टाचार पर भी रोक लगना जरूरी है। चूंकि हम यह सवाल नहीं उठाते, इसलिए जनता भ्रष्टाचार-विरोधी लड़ाई से निर्लिप्त रह जाती है। एक बात और समझने की जरूरत है। वह यह कि जब तक असीमित उपभोग की छूट रहेगी, तब तक हम लूट की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सकते।

विचार

विवाद में न फंसे कांग्रेस

नए अध्यक्ष के चयन के लिए सोमवार को बुलाई गई कांग्रेस कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक नेताओं की कलह का जरिया बन गई। कांग्रेस को समझना होगा कि उसका मुकाबला भाजपा से है। अगर उसका यही रवैया रहा तो पार्टी अपनी दिक्कतें खुद बढ़ाएगी।

नए अध्यक्ष के चयन के लिए बुलाई गई कांग्रेस कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक नेताओं की कलह का जरिया बन गई। बैठक से पहले सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के मुद्दे पर घमासान मच गया। मनमोहन सिंह, एके एंटनी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं को खूब खरी-खोटी सुनाई। बात यहां तक आ गई दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी तो एक और सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर हैंडल से अपनी कांग्रेसी पहचान मिटा दी। दरअसल, यह सब राहुल गांधी के उस बयान की प्रतिक्रिया में हुआ, जिसमें उन्होंने सोनिया को चिट्ठी लिखने वालों पर भाजपा के साथ सांठगांठ का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिनमें कांग्रेस कार्यसमिति के कई सदस्यों के अलावा पांच पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

चिट्ठी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्रियों-आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, सांसद विवेक तनखा, मुकुल वासनिक और जितिन प्रसाद के नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों भूपिंदर सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भटट्ल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी और मिलिंद देवड़ा के भी हस्ताक्षर हैं। राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली और कौल सिंह ने भी चिट्ठी को समर्थन दिया है। यह पत्र रविवार को सामने आया था। इसके बाद सोनिया गांधी ने पत्र का जवाब देकर कहा कि उनका एक साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब पार्टी नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दे। सोमवार की बैठक में जो भी हुआ, उसके संकेत रविवार को सोनिया गांधी के इस जवाब से मिल गया था, पर मामला इस कदर बिगड़ेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेसी खेमे में चल रही खटपट अब तक बंद कमरे में थी, आज देश के सामने है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राजस्थान के अशोक गहलोत, छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया और राहुल के नेतृत्व में भरोसा जताया और इस बात पर जोर दिया कि गांधी परिवार ही पार्टी को एकजुट रख सकता है। मगर नेताओं की रस्साकशी ने कांग्रेस को सोनिया और राहुल दो धड़ों में बांट दिया है। नेता आज कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि सोनिया या राहुल के साथ हैं। गुटों में बंटी कांग्रेस की इस हालत पर भाजपा को वार करने का मौका खुद पार्टी ने ही दिया है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि नेतृत्व के मुद्दे पर आज उसने जो फजीहत कराई है, उसका संदेश अच्छा नहीं गया है। कांग्रेस का मुकाबला आज उस भाजपा से है, जिसकी कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। उनके पीछे पूरी फौज है। अगर कांग्रेस को भाजपा से आगे निकलना है, तो इस तरह की राजनीति से बाहर आना होगा, वरना उसके दुर्दिन शुरू हो जाएंगे।

युवाओं के लिए सुगमता का द्वार

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के रूप में ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी नियुक्ति सुधार के पारित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के बीच पहुंचे और कहा कि यह पहल करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे तमाम तरह की परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कीमती समय और संसाधनों की भी बचत होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनआरए की स्थापना से पारदर्शिता को भी काफी बढ़ावा मिलेगा जो उनके प्रशासन मॉडल का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नामक मल्टी-एजेंसी संस्था ग्रुप बी और ग्रुप सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वर्तमान में सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती हैं जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। हर साल केंद्र सरकार में लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित होते हैं। लेकिन अगले साल से एनआरए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा और सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर कोई भी संबंधित एजेंसी में रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। इस प्रकार समय और संसाधनों की बचत के अलावा यह रोजगार की तलाश करने वाले लाखों लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधारों के लिए कई कई कदम उठाए गए और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में दस्तावेजों को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराने की प्रथा को खत्म करते हुए स्व-सत्यापन का प्रावधान किया गया।

इसके अलावा इसमें निचले स्तर के कर्मचारियों के चयन के लिए साक्षात्कार को खत्म करना, 1500 से अधिक अप्रचलित नियम और कानूनों को समाप्त करना, आईएएस अधिकारियों के लिए उनके करियर की शुरुआत में तीन महीने के लिए केंद्र सरकार में सहायक सचिव के रूप में अनिवार्य कार्यकाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन और प्रधानमंत्री के उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नया प्रारूप शामिल हैं। लेकिन एनआरए एक अनोखा मॉडल है क्योंकि इसे सरकारी भर्ती प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव सुनिश्चित होगा। साथ ही यह सरकार के युवा रोजगार आकांक्षियों के

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना देश के उन युवाओं के लिए मील का पत्थर होगा, जो एक समय में कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और संसाधन के अभाव में विफल हो जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी, मगर फैसला अटका था। नई शिक्षा नीति के बाद नौकरी की नई नीति नि:संदेह बेहतर परिणाम लेकर आएगी।

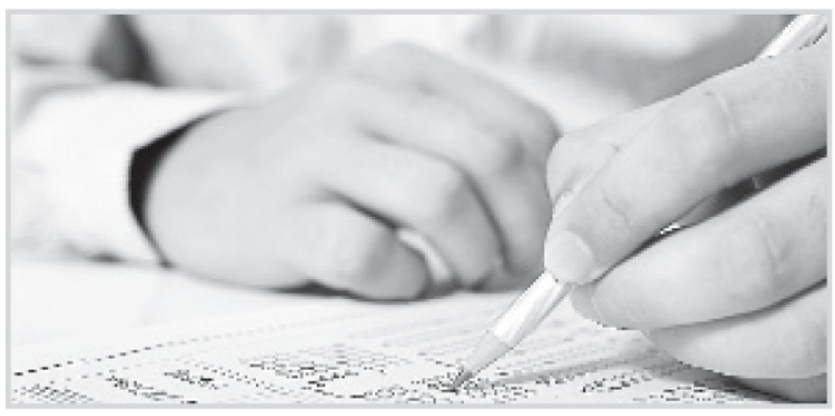

लिए जीवन की सुगमता संबंधी मंत्र के अनुरूप भी है जिसके तहत सरकार उम्मीदवारों के लिए भर्ती, चयन व नौकरी बदले में सुगमता सुनिश्चित करना चाहती है। कुल मिलाकर, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा बोझ होता है क्योंकि इसमें अनावश्यक खर्च, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा और जगह संबंधी तमाम समस्याएं भी शामिल होती हैं। इसलिए, एनआरए अपनी मूल भावना में उम्मीदवारों के लिए कम लागत और सुविधा का एक संयोजन है।

देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र तक दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों के पहुंचने के लिए सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। साथ ही देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संबंधी बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान से समीप के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आसानी हो सके। यह विशेष तौर पर पहाड़ी, ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय में विभिन्न केंद्रों पर इस तरह की परीक्षा देने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन अब उन्हें लागत, प्रयास, सुरक्षा आदि के संदर्भ में काफी फायदा होगा। नौकरी के अवसरों को लोगों के करीब ले जाना एक बुनियादी कदम है जो युवाओं के लिए जीवन जीने में सुगमता को बेहतर करेगा। एनआरए के जरिये ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करने की भी परिकल्पना की गई है और इसका 24×7 हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण पोर्टल होगा।

एनआरए-सीईटी की संयुक्त पहल की एक अन्य बड़ी विशेषता यह है कि उम्मीदवार का सीईटी स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से अगले तीन साल की अवधि के लिए वैध रहेगा। सर्वश्रेष्ठ वैध स्कोर को ही उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। सीईटी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी लेकिन वह उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा पर निर्भर करेगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक होगा क्योंकि फिलहाल उन्हें इन परीक्षाओं की तैयारी करने और उनमें शामिल होने के लिए हर साल काफी मेहनत करनी पड़ती है जिससे उनके समय और धन की बर्बादी होती है। एनआरए सभी गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्चतर माध्यमिक और मैट्रिकुलेट उम्मीदवारों के लिए तीन स्तरों के लिए एक अलग सीईटी आयोजित करेगा। वर्तमान में उन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड व बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा किया जाता है।

सीईटी स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर अंतिम चयन के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा विशिष्ट स्तरों पर अलग-अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम एक जैसा होगा जो मानक होगा। इससे अभ्यर्थियों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में उन्हें अलग-अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। उम्मीदवारों को एक साझा पोर्टल पर पंजीकरण करने और केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य एक ऐसे चरण तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार खुद अपनी पसंद के केंद्रों पर परीक्षा दे सकें। सीईटी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होगी। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले के लोगों को परीक्षा देने में काफी सुविधा होगी।

हिंदी-अंग्रेजी के अलावा 12 अन्य भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। शुरुआत में सीईटी स्कोर का उपयोग तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। जबकि समय के साथ इसे केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद है। यदि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियां भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप दीर्घावधि में सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

ट्विटर

राहुल ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे सूचित किया कि उन्होंने वो कभी नहीं कहा था जो उनके हवाले से बताया गया है। ऐसे में मैं अपना पहले का ट्वीट वापस लेता हूं।

कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता

कांग्रेस को सही दिशा में लाने की बात करें तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भाजपा से मिले हैं। सिब्बल और आजाद जैसे नेताओं पर पार्टी को भरोसा नहीं।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सत्यार्थ

सच्चा चिकित्सक

एक बार की बात है। रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन को एक खास रसायन बनाने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। उन्होंने अपने परिचितों व कुछ पुराने शिष्यों को इस बारे में बताया। इन लोगों ने कई युवकों को उनके पास भेजा। तब आचार्य ने सबकी थोड़ी-बहुत परीक्षा लेकर उनमें से दो युवकों को इस कार्य के लिए चुना। दोनों को एक-एक रसायन बनाकर लाने को कहा। पहला युवक दो दिन बाद ही रसायन तैयार कर लाया। नागार्जुन ने उससे पूछा-तुमने बड़ी जल्दी रसायन तैयार कर लिया, कुछ परेशानी तो नहीं आई? युवक बोला- आचार्य! परेशानी तो आई है, मेरे माता-पिता बीमार थे, पर मैंने आपके आदेश को महत्व देते हुए रसायन तैयार किया है। आचार्य ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा युवक बिना रसायन लिए लौटा एवं बोला-आचार्य क्षमा करें। मैं रसायन नहीं बना पाया, क्योंकि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया, जो बीमार था। मैं उसको अपने घर ले गया और उसका इलाज करने लगा। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। अब आप आज्ञा दें तो मैं रसायन तैयार करके शीघ्र ही ले आऊंगा। नागार्जुन ने मुस्कराते हुए कहा-वत्स। तुम्हें अब रसायन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से तुम मेरे साथ रहकर काम कर सकते हो। फिर वह पहले युवक से बोले-बेटा! अभी तुम्हें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, यह अच्छी बात है। इससे मुझे प्रसन्नता हुई, परंतु यह मत भूलो कि सच्चा चिकित्सक वह है, जिसके भीतर मानवीयता भरी हो। अगर किसी को तत्काल सेवा और उपचार चाहिए तो चिकित्सक को सभी आवश्यक कार्य छोड़कर उसकी सेवा में लग जाना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शीर्ष सहयोगी केलीएन कोनवे ने छोड़ा व्हाइट हाउस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे प्रभावशाली एवं लंबे समय तक सेवा देने वाली सलाहकार केलीएन कोनवे ने रविवार को घोषणा की कि वह महीने के अंत में व्हाइट हाउस से रुखसत हो जाएंगी।

कोनवे 2016 में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में ट्रंप की अभियान प्रबंधक थीं। वह पहली महिला थीं, जिन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी जगह बनाई और फिर राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार बनीं। उन्होंने अपने फैसले की सूचना ट्रंप को ओवल ऑफिस में दी। कोनवे ने रविवार रात पोस्ट किए अपने त्यागपत्र में कहा कि वह अपने चार बच्चों के साथ समय बिताना चाहती हैं। उनके पति, जॉर्ज कोनवे राष्ट्रपति ट्रंप के मुखर आलोचक बन गए हैं और उनका परिवार वाशिंगटन में अफवाहों के बाजार का विषय बन गया है।

इस हफ्ते रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगी संबोधित

उन्होंने लिखा कि अभी के लिए और मेरे प्यारे बच्चों के लिए ड्रामा कम, ममा (मां) ज्यादा होगी। हालांकि, वह इस हफ्ते होने वाले रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने वाली हैं। उनके पति, जो पेशे से वकील हैं और जिन्होंने 2016 अभियान के बाद ट्रंप को नापसंद करना शुरू कर दिया था और लिंकन प्रोजेक्ट के सदस्य बन गए थे, जो कि ट्रंप को हराने के लिए समर्पित रिपब्लिकनों का समूह है। राजनीतिक रूप से विरोधात्मक शादी से वाशिंगटन डीसी और ऑनलाइन बहुत अटकलें लगाई गईं। जॉर्ज कोनवे ने भी रविवार को घोषणा की कि वह ट्विटर और लिंकन प्रोजेक्ट दोनों से कुछ समय के लिए नदारद रहेंगे।

न्यूज

एसजीपीसी अध्यक्ष बने बलजीत दादूवाल

बठिंडा, (एजेंसी)। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल सोमवार को बठिंडा के तलवंडी साबो स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब पर नतमस्तक हुए। उन्होंने सोमवार को जत्थेदार पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त सरबत खालसा से विनती की है कि उनकी जगह किसी और को जत्थेदारी दे दी जाए। जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। 2014 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काफी विवादों के बाद हरियाणा विस में बने एक्ट के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनी थी।

एयरबेस उड़ाने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार

अंबाला, (एजेंसी)। हरियाणा अंबाला पुलिस ने स्थानीय अंबाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर महज 48 घंटे में यह मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक की शिनाख्त विशाल के रूप में की गई है। उसे अंबाला के विजयरत्न चौक से गिरफ्तार किया गया। उसी ने धमकी भरा पत्र लिखा था। पुलिस के अनुसार यह युवक ओएलएक्स पर ठगी का शिकार हो चुका है और जिन लोगों ने इसे ठगा था उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। इतना ही नहीं इस युवक ने धमकी भरा पत्र जिस महिला के नाम से लिखा था उसकी पड़ताल भी पुलिस ने पूरी कर ली है।

किम जोंग उन की हो गई मौत, एक्सपर्ट का दावा

प्योंगयांग, (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य के बारे में दुनियाभर के लोग जानना चाहते हैं। किम जोंग के कोमा में चले जाने की अटकलों के बीच एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि तानाशाह की मौत हो गई है। 2011 में सत्ता संभालने वाले किम की पिछले कई महीनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी से अटकलों को बल मिला है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उत्तर कोरिया की अक्सर यात्रा करने वाले एक पत्रकार रॉय कैली ने दावा किया है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। उत्तर कोरिया में इस पर इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि वहां के निवासी भी नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। वहां बड़े बदलाव जैसे किम की बहन को वास्तविक डिप्टी कमांड देना इशारा करता है कि देश में कुछ चल रहा है।

अमेरिका में कोरोना के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट को मंजूरी

वाशिंगटन, (एजेंसी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोन्वलेसेंट प्लाज्मा से उपचार को अधिकृत करने की घोषणा की। इस कदम को वह कामयाबी बता रहे हैं, उनके शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे उम्मीदों भरा बताया है। जबकि अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी खुशी मनाने से पहले इस पर और अध्ययन जरूरी है। यह घोषणा तब की गई है जब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने शिकायत की है कि खाद्य व औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से बीमारी के लिए टीका और उपचार स्वीकृत करने में राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित देरी की जा रही है, जिस वजह से ट्रंप के पुनर्निर्वाचन की संभावनाएं घट रही हैं।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई

पाक ने एक और आंतकी संगठन किया प्रतिबंधित

इस्लामाबाद ■ एजेंसी

पाकिस्तान सरकार ने खातम-उल-अंबिया नामक एक और आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।

माना जाता है कि खातम-उल-अंबिया को अंसारुल हुसैन से जुड़ा संगठन माना जाता है, जो आमतौर दाएश के नाम से जाने जाने वाले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह से लड़ने के लिए शिया युवाओं की भर्ती करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के अंत में अंसारूल हुसैन को प्रतिबंधित किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तरफ से ब्लैकलिस्ट किए जाने से बचने की कोशिश के तहत इन आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इससे संबंधित नई सूची जारी की है।पाकिस्तान सरकार ने 21 अगस्त को दाएश, अल कायदा और तालिबान से जुड़े 88 आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून, 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था।

चल -अचल संपत्तियां जब्त करने के आदेश

पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की सभी तरह की चल और अचल संपत्तियां जब्त करने के आदेश भी दिये हैं। इसके साथ ही आतंकवादियों के बैंक खातों के फ्रीजिंग के आदेश भी दिये गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन आतंकवादियों के वित्तीय संस्थानों के जरिए पैसे स्थानांतरित करने, हथियारों को खरीदने और विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एफएटीएफ की अगली समीक्षा बैठक आगामी अक्टूबर माह में होनी है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का नाटक कर रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और आरबीआई से जवाब

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को गूगल पे द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जवाब मांगा। याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

मामला गूगल पे के विरुद्ध याचिका का

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने याचिका को लेकर विभागों के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है। याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा (विवरण) का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

नीट-जेईई एग्जाम कराने पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, नसबंदी के फैसले से की तुलना

नई दिल्ली ■ एजेंसी

जेईई मेन और नीट 2020 एग्जाम को लेकर देशभर में स्टूडेंट्स का विरोध देखने को मिल रहा है। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां शीर्ष अदालत ने जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने परीक्षाएं आयोजित करने के फैसले को राजनीतिक चूक करार दिया है। यहां तक कि उन्होंने इसकी तुलना नसबंदी के फैसले से कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है परीक्षाएं टालने की मांग

इंदिरा सरकार ने किया था नसबंदी का फैसला:

सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए कहा कि अगर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो ये भारी राजनीतिक चूक होगी। ये फैसला सरकार को इसी तरह प्रभावित कर सकता है, जैसा 1977 में नसबंदी के फैसले ने इंदिरा गांधी सरकार को किया था।

वोटर भूलेंगे नहीं...

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वोटर की याद्दाश्त काफी तेज होती है और वे इस बात को भूलेंगे नहीं। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती। जेईई मेन एग्जाम 1 से 6 सितंबर तक चलेंगे, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।अब भी देशभर के कई हिस्सों में स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि नीट की परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट की परीक्षा के लिए गाइडलाइंस और जेईई मेन 2020 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष लेंगे निर्णय

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने के आदेश दिया है। न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने सोमवार को भाजपा के विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिए। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को मामला तय करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा श्री दिलावर की याचिका को रद्द किये जाने के आदेश को भी अपास्त किया।

मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश

उल्लेखनीय है कि श्री दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका लगाई, जिसे अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था। इसके बाद श्री दिलावर ने इसे न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया था। उधर श्री दिलावर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य बताते हुए कहा कि इस बारे में कानूनी सलाह लेकर चर्चा की जाएगी कि आगे क्या करना है।

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की तरफ से कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव कराने को लेकर जारी बृहद दिशा-निर्देश को सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

गृह मंत्रालय के परिपत्र के विपरीत बताया

चुनौती में इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के परिपत्र के बिल्कुल विपरीत बताया गया, जिसमें ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक है। ईसीआई की तरफ से पिछले शुक्रवार को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं को दास्ताने मुहैया कराए जाएंगे और पृथक-वास में रह रहे कोविड-19 के रोगियों को मतदान के दौरान अंतिम समय में वोट डालने की अनुमति होगी। ईसीआई के दिशा-निर्देशों के खिलाफ एक जनहित याचिका में मसौदा संशोधन दायर किया गया है।

दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरे हो रहे हैं रिश्ते

चीन ने पाकिस्तान को बेचा अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज

बीजिंग ■ एजेंसी

चीन ने रविवार को पाकिस्तान के लिए एक लड़ाकू जहाज लॉन्च किया है। चीन द्वारा बेचे जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है। पाकिस्तान को भेजे जाने वाला ये पहला युद्धपोत है, इसके अलावा चीन पाकिस्तान को तीन युद्धपोत और भेजने वाला है।

पाकिस्तानी लोकल मीडिया का कहना है कि टाइप 054ए/पी एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है, जो अब तक ऐसा सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है, जो चीन ने किसी विदेशी सेना को बेचा है। वहीं चीनी मीडिया ने बताया है कि इस लड़ाकू जहाज से पाकिस्तानी नौसेना के युद्ध की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

पाकिस्तान को चीन भेजेगा चार लड़ाकू जहाज: उम्मीद की जा रही है कि चीन से वर्ष 2021 तक पाकिस्तान को ऐसे तीन और लड़ाकू जहाज भेजे जाएंगे। चीन के शंघाई के स्वामित्व वाली हडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में रविवार को एक लॉन्च का आयोजन किया गया था, जिसमें नौसेना के बड़े अधिकारी शामिल थे। शिपयार्ड देश में सबसे बड़े बिल्डर, चीन स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन की कंपनी है। ये लॉन्च पाकिस्तान के विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी की उस चर्चा के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारतीय कश्मीर क्षेत्र को लेकर बात की।

भारत अपने दोनों पड़ोसियों पर बनाए हुए है कड़ी नजर : राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी एक बैठक के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से रिकॉर्ड संदेश में पाकिस्तान को एक अच्छा भाई और एक अच्छा साथी बता चुके हैं। भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से ही सीमा विवाद को लेकर लगातार जूझ रहा है और इसलिए भारत अपने दोनों पड़ोसियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

लड़ाकू जहाज की खास बातें

स्थानीय समाचार वेबसाइट ifeng.com ने बताया कि यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान ने 054ए/पी को एफ-22पी फ्रिगेट के उत्तराधिकारी के रूप में खरीदा है और एफ-22पी फ्रिगेट, 053एच3 फ्रिगेट के आधार पर ये चीन द्वारा विकसित एक निर्यात मॉडल है। चीन 054 ए फ्रेट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 054ए मॉडल चीनी नौसेना का बेस्ट फ्रीगेट है। इस लड़ाकू विमान में 4 हजार टन मैट्रिक का डिस्प्लेसमेंट है और इसमें अच्छे रडार और मिलाइलों लो की सुविधा है। टाइप 054 ए एक मल्टी-रोल फ्रिगेट है, इस लड़ाकू जहाज को चीनी नौसेना की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। पीएलए के नेवल मिलिट्री स्टडीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ शोधकर्ता काओ वेइदॉन्ग ने अखबार को बताया कि ऐसा लगता है कि नए जहाज पर सभी हथियार और रडार चीन में बनाए जाएंगे जो उद्योग में हमारी प्रगति, तकनीक, क्षमता और पाकिस्तानी नौसेना के आत्मविश्वास को दर्शाता है।

एयरोस्पेस नॉलेज पत्रिका ने बताया जेएफ-17 ब्लॉक 3 विमान के बारे में

चीन और पाकिस्तान के सैन्य संबंध हाल के वर्षों में तेजी से गहरे हुए हैं। उदाहरण के लिए, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर संयुक्त रूप से उन्नत लड़ाकू क्षमताओं के साथ विकसित लड़ाकू विमान के नए संस्करण बनाए। 2020 में इस्लामाबाद द्वारा इनका पहला बैच स्थापित किया जाना है। एयरोस्पेस नॉलेज पत्रिका ने जनवरी में एक रिपोर्ट में कहा कि जेएफ-17 ब्लॉक 3 विमान को दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चेंगदू से ऊपर उड़ाया गया था। सिंगल-इंजन, मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

पत्नी को लेकर सवाल पूछने पर भड़क गए ब्राजील के राष्ट्रपति

पत्रकार को दी धमकी- मन करता है तुम्हें घूसा मारूं

नई दिल्ली ■ एजेंसी

कोरोना संक्रमण काल में अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो एक बार फिर से अपने विवादास्पद बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने रविवार को एक पत्रकार को सबके सामने पंच मारकर मुंह तोड़ने की धमकी दे दी डाली। दरअसल, पत्रकार ने बस उनसे एक योजना से जुड़े भ्रष्टाचार में उनकी पत्नी के लिंक के होने के दावों के बारे में सवाल किया था।

कोरोना काल में बयानों को लेकर विवाद में रहे हैं जायर बोलसोनारो

ओ ग्लोबो के रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने कहा कि मैं तुम्हारे मुंह पर घूंसे मारना चाहता हूं। हैरानी की बात है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने सबके सामने रिपोर्टर को ऐसा कहा। दरअसल, रिपोर्टर एक समूह का हिस्सा था, जो ब्राजीलिया में मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में अपनी नियमित रविवार की यात्रा के बाद जायर बोलसोनारो से मिला था। राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के इस धमकी से वहां मौजूद अन्य पत्रकारों ने उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, मगर जायर बोलसोनारो ने उनके विरोध-प्रदर्शन को अनदेखा कर वहां बिना कुछ बोले निकल गए।

पत्रकार ने राष्ट्रपति से क्या पूछा था?

दरअसल, ओ ग्लोबो के पत्रकार ने मैग्जीन क्रूजो में छपी एक खबर के आधार पर राष्ट्रपति से सवाल किया था। मैग्जीन में जो खबर छपी थी, उसमें ब्राजील की फर्स्ट लेडी मिशेल जायर बोलसोनारो और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर फैब्रिकियो क्यूरीज के लिंक को लेकर सवाल खड़े हैं। बता दें कि फैब्रिकियो क्यूरिज फिलहाल राष्ट्रपति के दोस्त हैं और उनके बेटे फ्लावियो बोलसोनारो के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में सीनेटर हैं।

इससे पहले भी दिया जायर बोलसोनारो ने विवादित बयान

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने कहा था कि कोरोना वायरस से कुछ लोग मरेंगे, निश्चित तौर पर कुछ लोग मरेंगे, यही जीवन है। आप सड़क दुर्घटना की वजह से कार फैक्टरी को बंद नहीं कर सकते।

अगले चार दिन हो सकते हैं खतरनाक, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारतीय मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए बहुत खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि किन राज्यों में मौसम का क्या अनुमान रह सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह 8.30 बजे को आधार मानते हुए अगले पांच दिन 25-28 अगस्त के लिए बेहद खतरनाक चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग चार रंगों में चेतावनी जारी करता है, जिसमें ग्रीन (हरा), येलो (पीला), ऑरेन्ज (नारंगी) और रेड (लाल) शामिल होते हैं। इसमें हरे रंग का मतलब होता है कि उस राज्य में चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, सब सामान्य है। पीले रंग का अर्थ होता है कि नजर बनाए रखें। ऑरेन्ज और रेड अलर्ट खतरनाक माना जाता है। किसी राज्य या क्षेत्र के लिए ऑरेन्ज अलर्ट का मतलब वहां तूफान या आंधी आ सकती है, तैयार रहें और रेड चेतावनी जारी की जाती है तो सरकार को एक्शन लेना है।

25 अगस्त के लिए पूर्वानुमान
- ओडिशा : रेड अलर्ट (चेतावनी)
- गुजरात, पश्चिम बंगाल : ऑरेन्ज अलर्ट (तैयार रहें)

26 अगस्त के लिए पूर्वानुमान
- ओडिशा : रेड अलर्ट (चेतावनी)
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल : ऑरेन्ज अलर्ट (तैयार रहें)

27 अगस्त के लिए पूर्वानुमान
- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड : ऑरेन्ज अलर्ट (तैयार रहें)

28 अगस्त के लिए पूर्वानुमान
- मध्यप्रदेश (कुछ इलाके), उप्र (कुछ इलाके) - ऑरेन्ज अलर्ट (तैयार रहें)

अलगाववाद — कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की निकली हवा

नया संगठन खड़ा करना चाहती थी आईएसआई

नईदिल्ली ■ एजेंसी

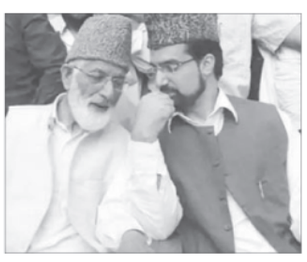

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के समानांतर एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगने लगा कि हुर्रियत से कश्मीरी लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। यह खुलासा एनआईए की चार्जशीट से हुआ है। आईएसआई ने यह काम इरफान शफी मीर को सौंपा था, जो कि घाटी में रहने वाले 31 वर्षीय वकील है। इरफान पर पाकिस्तान की आईएसआई और हिज्बुल के शीर्ष नेतृत्व दोनों को भरोसा था।

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कम से कम छह आईएसआई अधिकारियों का जिक्र किया है, जो कि इरफान मीर के साथ संपर्क में थे। इन छह के नाम उमर चीमा, ईशान चौधरी, फैजल, सोहेल अब्बास, अरबाज और शेख साहब हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी शफकत जतोई उर्फ हुसैन, जिन्हें इस साल जून में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इस्लामाबाद वापस लौटा दिया गया था, ने दो किस्तों पर इरफान शफी मीर को हाउ टू डिफेंस आयोजित करने के लिए 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह सभी बातें एनआईए की चार्जशीट में सामने आई हैं।

प्रोफेसर हमीदा नईम ने किया खंडन

प्रोफेसर हमीदा नईम ने बताया कि यह एक सफेद झूठ है। मैंने इस तरह के किसी सेमिनार में भाग नहीं लिया है। इरफान शफी मीर को घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने पूरी साजिश में महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि वह निर्देश और पैसों के लिए नियमित रूप से नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा करता था। उसे इस साल 11 जनवरी को शोपियां में जम्मू-कश्मीर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दविंदर सिंह और दो हिज्बुल आतंकवादियों - सैयद नावेद मुश्ताक उर्फ नावेद बाबू और रफी अहमद राथर के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 1993 में कश्मीरी अलगाववाद को एकजुट करने एक संयुक्त मोर्चे के रूप में गठित हुआ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पिछले दो वर्षों से कश्मीर में अप्रभावी है। इसके नेता सैयद अली शाह गिलानी ने इस साल जून में इस्तीफा दे दिया था। पिछले दो-तीन वर्षों में एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा अलगाववादी नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है, जिनमें से कई को जेल में बंद किया गया तो कई घर में नजरबंद हैं।

पंजाब सरकार द्वारा ड्राइविंग लायसेंस, आर.सी. और परमिटों की समय सीमा में वृद्धि-परिवहन मंत्री

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

जिन पंजाब निवासियों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लायसेंसों, आर.सीज़ या परमिटों की समय सीमा 1 फरवरी, 2020 से ख़त्म हो चुकी है और कोविड-19 के कारण वह अभी तक इनको रिन्यू नहीं करवा सके, उनके लिए एक अ%छी ख़बर है, जो ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और परमिट आदि की समय सीमा 1 फरवरी, 2020 के बाद या 31 दिसंबर, 2020 तक ख़त्म होनी है, को अब तारीख़ 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जाएगा। पंजाब की परिवहन मंत्री रज़िया सुल्ताना ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बने गंभीर हालातों के चलते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीते कल इस सम्बन्धी ताज़ा हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने

> "पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और सभी डी.सीज़ को निर्देश जारी; आम लोगों को तंग या परेशान न किया जाए"

कहा कि हिदायतों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988और सैंट्रल मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत बनाए जाने वाले दस्तावेज़ जैसे कि ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट आदि जिनकी समय सीमा 01 फरवरी, 2020 के बाद या 31 दिसंबर, 2020 तक ख़त्म होनी है, को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन हिदायतों संबंधी पत्र परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने पंजाब के डीजीपी को भेज दिया है। इसके अलावा एडीजीपी (ट्रैफ़िक), सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी एसएसपीज़ और परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे आम नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को कहा गया है कि उक्त हिदायतों के मद्देनज़र वाहनों की चैकिंग के दौरान जिन व्यक्तियों, ट्रांसपोर्टरों या अन्य संस्थाओं के ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या परमिट 1 फरवरी, 2020 के बाद रीन्यू नहीं करवाए गए हैं, उनको तंग या परेशान न किया जाए, क्योंकि नई हिदायतों के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ 31 दिसंबर, 2020 तक वैध माने जाएंगे।

पंजाब कैबिनेट द्वारा 11 और कॉन्स्टीटूएंट कॉलेजों को 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आवर्ती अनुदान मंज़ूर

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब में उच्च शिक्षा के मानक को और ऊँचा उठाने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा मंगलवार को 11 और कॉन्स्टीटूएंट कॉलेजों को वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 75.75 करोड़ रुपए का आवर्ती अनुदान मंज़ूर किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन कैबिनेट ने भविष्य में इन कॉलेजों के लिए प्रति कॉलेज प्रति वर्ष के लिए 1.5 करोड़ रुपए का नियमित बजट उपबंध करने की भी मंज़ूरी दे दी। इससे ऐसे कॉलेजों की संख्या 30 हो गई, जिनको राज्य सरकार द्वारा आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है।

इन कॉलेजों में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के तीन कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज धुरी (संगरूर), यूनिवर्सिटी कॉलेज बहादुरपुर (मानसा) और यूनिवर्सिटी कॉलेज बरनाला, गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज अमृतसर के छह कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज सुजानपुर, बाबा नामदेव यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज किशनकोट (गुरदासपुर), यूनिवर्सिटी कॉलेज फिल्लौर (जालंधर), यूनिवर्सिटी कॉलेज नकोदर (जालंधर) और यूनिवर्सिटी कॉलेज कलानौर (गुरदासपुर) और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के दो कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज फ़िरोज़पुर और यूनिवर्सिटी कॉलेज धर्मकोट (मोगा) शामिल हैं। यह अनुदान कॉलेजों के अध्यापकों को समय पर वेतन अदा करने को यकीनी बनाने के अलावा विद्यार्थियों को मानक शिक्षा मुहैया करवाने में सहायक सिद्ध होगा। इसी दौरान मंत्रीमंडल द्वारा एक अन्य फ़ैसले में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के साल 2018-19 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी।

धोनी क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक और महानतम कप्तानों में से एक-शाहीदी अफरीदी

स्पोर्ट्स प्लैनट

रिकी पोंटिंग से हुई टेलीफोन पर बातचीत का जल्द खुलासा करेंगे रविचंद्रन अश्विन

■ दुबई/ब्यूरो

भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्होंने नॉन स्ट्राइकर छोर पर गेंद करने से पहले आगे निकलने वाले बल्लेबाज को आउट करने के विवादास्पद मसले पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अपने कोच रिकी पोंटिंग से बात की लेकिन वह टेलीफोन पर हुई अपनी बातचीत के सार का अगले सप्ताह खुलासा करेंगे। अश्विन की टीम दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच पोंटिंग ने कहा था कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल से पहले बल्लेबाजों को आउट करने के इस विवादास्पद तरीके को लेकर इस भारतीय स्पिनर से बात करेंगे। तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अश्विन ने पिछले साल आईपीएल में इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर को नॉन स्ट्राइकर छोर पर क्रीज से काफी आगे निकलने के बाद रन आउट कर दिया था और तब कई ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया था। अश्विन दुबई पहुंच चुके हैं लेकिन पोंटिंग को अगले सप्ताह वहां पहुंचना है और इसके बाद वे आपस में बैठकर बात करेंगे।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''रिकी पोंटिंग अभी (दुबई) नहीं पहुंचे हैं। जब वह पहुंच जाएंगे तो हम उनके साथ बात करेंगे। हम फोन पर पहले ही बात कर चुके हैं। यह बातचीत बेहद दिलचस्प रही थी।'' इस स्पिनर ने कहा कि आमने सामने बातचीत करना बेहतर है क्योंकि आस्ट्रेलियाई लहजे की अंग्रेजी का अनुवाद में अर्थ का अनर्थ बन सकता है। उन्होंने कहा, ''कई बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी में आस्ट्रेलियाई संदेश अनुवाद में खो जाता है और हमारे पास भिन्न अर्थ के साथ पहुंचता है। यहां तक कि उनके कुछ मजाक समाचार बन जाते हैं। यह मामला भी ऐसा ही है और रिकी के साथ अपनी बातचीत का अगले सप्ताह मैं थोड़ा और खुलासा करूंगा।''

पोंटिंग ने कहा था कि उनकी अश्विन के साथ इस मसले को लेकर कड़ी बातचीत होगी और वह उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बल्लेबाजों को इस तरह से रन आउट करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि यह खेल भावना के विपरीत है। अश्विन ने सोमवार को बल्लेबाज के गेंद करने से पहले क्रीज से आगे निकल जाने पर गेंदबाज को 'फ्री बॉल' देने का सुझाव दिया और इस तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि बल्लेबाज को इस तरह से रन आउट करना गलत नहीं है।

दो और सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा-विजय इंदर सिंगला

अब तक राज्य के विभिन्न गाँवों से संबन्धित 10 शहीदों और आज़ादी संग्रामियों के नाम पर रखे स्कूलों के नाम - शिक्षा मंत्री

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने आज बताया कि राज्य के विभिन्न गाँवों से सम्बन्धित शहीदों और आज़ादी संग्रामियों को बनता सम्मान देने और उनकी याद शाश्वत बनाये रखने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 और सरकारी स्कूलों का नाम बदलने का फ़ैसला किया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये इससे पहले भी विभिन्न जिलों के 8 सरकारी स्कूलों का नाम बदल के शहीदों के नाम पर रखा जा चुका है।

विभिन्न जिलों के सात अन्य स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया, जिनमें पंजाब के चार बहादुर सपूत शामिल हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ निहत्थे लड़ते हुये अपनी जान कुर्बान की

श्री सिंगला ने बताया कि गुरदासपुर जिले के गाँव वील्हा बज्जू में सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल का नाम शहीद नायक कुलजिन्दर सिंह सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल रखा जा रहा है। शहीद नायक कुलजिन्दर सिंह ने श्रीनगर में साल 2005 में देश की रक्षा करते हुये अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह जिला संगरूर के गाँव मटरां में सरकारी मिडल स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स. हजूरा सिंह सरकारी मिडल स्कूल रखा गया है, जो सेवा सिंह ठीकरीवाला के नेतृत्व अधीन चल रही प्रजा मंडल लहर के प्रमुख नेता थे। स. हजूरा सिंह ने किसान सभा का भी नेतृत्व किया और दो बार, डेढ़ साल और दो साल की जेल काटी।

श्री सिंगला ने कहा, ''कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पिछली सरकार की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जिला मानसा के गाँव कुसला में सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल का नाम बदल कर गाँव के कारगिल युद्ध के शहीद के नाम पर रखने का सिर्फ ऐलान किया था परन्तु हमारी सरकार ने हाल ही में इस स्कूल का नाम बदला है और इस स्कूल को शहीद नायक निर्मल सिंह सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल का नाम दिया गया है।'

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी तरह विभिन्न जिलों के सात अन्य स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया, जिनमें पंजाब के चार बहादुर सपूत शामिल हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ निहत्थे लड़ते हुये अपनी जान कुर्बान की।

उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शहीद सिपाही गुरबिन्दर सिंह सरकारी हाई स्कूल तोलावाल (संगरूर), शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह सरकारी प्राईमरी स्कूल, सील (पटियाला), शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह सरकारी मिडल स्कूल, भोजराज (गुरदासपुर) और शहीद गुरतेज सिंह सरकारी मिडल स्कूल, बीरेवाल डोगरा (मानसा) शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि और तीन स्कूल शहीद मनिन्दर सिंह अत्तरी सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल (लड़के) दीनानगर (गुरदासपुर), शहीद जैमल सिंह सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल घलोटी (मोगा) और शहीद सुखजिन्दर सिंह सरकारी हाई स्कूल, गंडीविंड धत्तल (तरन तारन) शामिल हैं।

Microsoft ने इन 3 भाषाओं में शुरू की 'न्यूरल टेक्स्ट-टू-स्पीच' सेवा

■ हैदराबाद/ब्यूरो

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी 'न्यूरल टेक्स्ट-टू-स्पीच' सेवा में भारतीय अंग्रेजी और हिंदी के दो विकल्प जोड़े हैं। इसी के साथ कंपनी ने इस सेवा में कुल 15 नयी वैश्विक भाषाओं को जोड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक सुंदर श्रीनिवासन ने कहा, ''हमारी 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' सेवा ने लोगों एवं संगठनों को सशक्त करने और सूचना के लोकतांत्रीकरण में अहम भूमिका अदा की है।'' 'टेक्स्ट-टू-स्पीच' (टीटीएस) सेवा मोबाइल एवं कंप्यूटर पर दिखने वाली लेख सामग्री को वास्तविक व्यक्ति की आवाज में सुनाने का काम करती है। न्यूरल टीटीएस एक कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-एआई) आधारित प्रणाली है। यह एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेस का हिस्सा है। भारतीय अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ कंपनी ने अरबी (मिस्र और सऊदी अरब), दानिश, फिनिश, कैटलन, पोलिश, डच, पुर्तगाली, रूसी, थाई, स्वीडिश और चाइनीज में भी इस सेवा की शुरूआत की है। माइक्रोसॉफ्ट टीटीएस 45 से अधिक और बोलियों में सेवा देती है।

जालंधर पुलिस डिवीजन नंबर 1 ने तीन व्यक्तियों को नाजायज हथियार अपने पास रखने के संबंध में गिरफ्तार किया

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

जालंधर पुलिस डिवीजन नंबर 1 को सफलता तब हासिल हुई जब वह तिथि 19-08-2020 को वेरका मिल्क प्लांट चौंक पर अपनी पुलिस पार्टी समेत नाके पर चेकिंग कर रहे थे तभी उनको एक गुप्त सूचना मिली की मोहन कुमार उर्फ मंदीप पुत्र रामयन राय वासी गुरु अमरदास नगर जालंधर जिस के पास नजायज हथियार है जो लॉकडाउन की उल्लंघना करते हुए अपने सप्लेंडर मोटरसाइकल पर स्वार कालिया कलोनी की तरफ हथियार लेकर घूम रहा है पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ डिवीज़न नंबर 1 में मुकदमा नंबर 141 तिथि 19-08-2020 आई पी सी की धारा के अधीन 188 और सेक्शन

25,27,54,59 आर्म्स एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया और दोषी मोहन कुमार को अदालत में पेश कर पुलिस द्वारा चार दिन की रिमांड हासिल की गयी ।

इस दौरान मोहन कुमार का संबंध पटना बिहार से होने के कारण पूछताछ के लिए यह मामला सी आई ऐ स्टाफ 1 को दिया गया और सी आई ऐ स्टाफ 1 द्वारा गहराई से पूछताछ करने के दौरान मोहन कुमार ने अपने दो साथियो बारे जानकारी दी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके उनके पास से एक पिस्तौल 315 बोर के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद किया।

दोषी मोहन ने बताया की वह यह हथियार यू पी से सस्ती कीमत पर लेकर आता था और महंगे दामो पर बेचता और मोहन कुमार ने बताया की वह यह हथियार सात महीने पहले अपने दोस्त परमिंदर सिंह उर्फ बिटू के साथ मिलकर दोषी सुखबीर सिंह को 20 ह?ार रूपए में बेचा था जिनको 21-08-2020 को पुलिस ने अपनी हिरासत मे ले लिया है और मौके पर बरामद हुए सामान में एक पिस्टल 9 म म ,एक पिसतोल 315 बोर साथ में 1 जिंदा कारतूस और एक मोटर साइकल पी बी 32 एफ 4015 शामिल है ।

पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल में हार के बाद रोने लगे थे नेमार तो वहीं उदास बैठे रहे मबापे

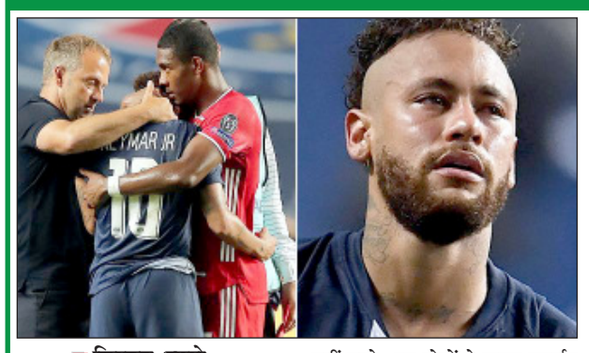

■ लिस्बन/ब्यूरो

नेमार और काइलिन मबापे पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की चैंपियन्स लीग फाइनल में बायर्न म्यूनिख के हाथों 1-0 से हार के बाद बेहद निराश थे क्योंकि उन्हें आखिर तक इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। ये दोनों खिलाड़ी पीएसजी की बेंच पर अगल बगल में बैठे थे। मबापे के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी जबकि नेमार अपने आंसू नहीं रोक पाये और उन्होंने अपना मुंह ढक दिया। पीएसजी का चैंपियन्स लीग का अपना पहला खिताब जीतने का इंतजार एक साल और बढ़ गया क्योंकि नेमार और मबापे फाइनल में अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इन दोनों ने लचर प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी टीम के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पहली बार यूरोपिय क्लब टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया था लेकिन खिताबी मुकाबले में वे किसी भी समय अपने असली रंग में नहीं दिखे। पीएसजी ने पहली बार चैंपियन्स लीग जीतने के लिये इन खिलाड़ियों पर करोड़ों डालर खर्च किये लेकिन निर्णायक मैच में उनका जादू नहीं चला। मबापे और नेमार दोनों को पहले हाफ में मौके मिले लेकिन वे उसका फायदा नहीं उठा पाये। दूसरे हाफ में तो वे किसी भी समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाये। बायर्न ने 59वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली थी और पीएसजी को वापसी दिलाने का जिम्मा इन दोनों खिलाड़ियों पर था। पीएसजी के कोच थामस टचेल ने कहा, ''पिछले कुछ सप्ताहों में हमने वह सब कुछ किया जो जीत के लिये जरूरी होता है। फुटबॉल में आपको यह स्वीकार करना होगा कि भाग्य भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारे पास मौके थे लेकिन हम गोल नहीं कर पाये, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह किसी की गलती है।''

नेमार के पास 18वें मिनट में गोल करने का मौका था लेकिन उनका शॉट नेयुर ने रोक दिया। मबापे को भी बायर्न के गोलमुख के पास दो मौके मिले लेकिन वे विरोधी टीम के रक्षकों को नहीं छका पाये। यह जोड़ी इसके बाद दूसरे हाफ में पीएसजी को मिले सर्वश्रेष्ठ अवसरों को भी नहीं भुना सकी। मबापे 72वें मिनट में तेजी से गेंद लेकर आगे बढ़े लेकिन वे गोल करने में नाकाम रहे। नेमार के पास इंजुरी टाइम में मौका था लेकिन उन्हें भी असफलता ही देखने को मिली।

सोनू सूद और पीएचडी चैम्बर्स पंजाब के चेयरमैन करण गिल्होत्रा ने वंचित छात्रों की मदद को बढ़ाया हाथ

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

रियल स्टार सोनू सूद और चंडीगढ़ के एक युवा उद्यमी और समाजसेवी करण गिल्होत्रा के साथ कई नेक काम करने के बाद दोनों ने निस्वार्थ भावना से उन छात्रों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जो मौजूदा हालात में आर्थिक तंगी के चलते ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। इस संबंध में उन्होंने दोस्ती की मदद से एक अभियान की शुरुआत हरियाणा के रिमोट एरिया मोरनी से की है। करण गिल्होत्रा ने जब देखा कि छात्र वर्ग ऑन लाईन की शिक्षा से वंचित है तो उन्होंने उनका वास्तविक दर्द समझते हुए सरकारी हाई स्कूल के छात्रों को स्मार्ट फोन उपहार स्वरूप भेंट किए। करण गिल्होत्रा और सोनू सूद ने छात्रों को स्मार्ट फोन प्रदान करने के बाद वर्चुअल इवेंट के माध्यम से छात्रों से बातचीत की। करण गिल्होत्रा जो सोनू सूद के करीबी दोस्त है और पंजाब पीएचडी चैम्बर्स आफ कामर्स एड इंडस्ट्री के चेयरमैन भी है कोरोना महामारी के बीच लोगों की मदद में जुटे सोनू सूद के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं। दोनो युवा ने आन्ध्र प्रदेश में किसान परिवार को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए न केवल ट्रैक्टर भेट किया बल्कि पंजाब में जहरीली शराब के चलते जान गंवाने वाले चार बच्चो को गोद लिया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 27 प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँचने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है और लगभग 84 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन

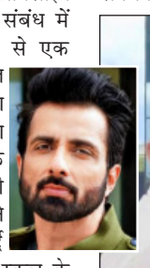

कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं राष्ट्रीयव्यापी लॉकडाउन के बाद देश भर के अधिकांश स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे है और छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद करते है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते हुए करण गिल्होत्रा ने कहा मैं अपने दोस्त सोनू सूद से बेहद प्रभावित हूँ कि वह मानवता की सेवा के लिए सदैव आगे रहते हैं जब हमें पता लगा कि हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में छात्र स्मार्ट फोन के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है तो उन्होंने अभिनेता और वास्तविक जीवन के नायक सोनू सूद ने कहा युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हम इन छात्रों की मदद करने के लिए अपनी और से कुछ कर पाए। मैं सही मायने में इन बच्चों को अपनी ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढाने में समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए करण का बहुमूल्य योगदान है। वह मेरे लिए ताकत का एक बड़ा स्तंभ रहा है और संकट के दौरान अपने निस्वार्थ योगदान के लिए वह प्रशंसा का पात्र है।

डिवीज़न नंबर 4 की पुलिस ने दो एक्टिवा समेत दो चोरों को किया काबू

■ जालंधर ब्रीज/ब्यूरो

पुलिस डिवीज़न नंबर 4 ने चोरी की वारदात को एक दिन में ही सुलझाया और बताया सिविल हस्पताल में तिथि 18-08-2020 को तकरीबन वक्त सुबह 9 बजे बच्चा वार्ड की पार्किंग में से एक्टिवा नंबर पी बी 08 ए वाई 1698 चोरी होने का मामला सामने आया वहीँ एक्टिवा के मालिक अम्बा दत्त पुत्र हरी दत्त लिखारी वासी सिविल हस्पताल कॉलोनी जालंधर ने पुलिस को बताया की वह अपनी एक्टिवा को पार्किंग में लगा कर अंदर गया जब वह बाहर आया तो उसकी एक्टिवा वहां पार्किंग में मौजूद नहीं थी। ए.एस.आई. सुरिन्दर पाल ने उसके बयानों के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश दौरान अश्वनी कुमार पुत्र सोहन

लाल वासी संतपुरा सुल्तानपुर कपूरथला और बलविंदर सिंह (बिट्टू)पुत्र मोहन सिंह वासी 244/1 मुहबत नगर पुलिस डिवीजन कपूरथला के पास से चोरी हुई 2 एक्टिवा नंबर पी बी 08 ए वाई 1698 और पी बी 08 ई जे 8718 चोरी हुई एक्टिवा बरामद की गई और दोनों को गिरफ्तार किया गया ।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक बनाने का लक्ष्य, 12 घंटे में तय होगी दूरी : गडकरी

भोपाल/ब्यूरो

केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे 2023 तक बनाने का लक्ष्य है। गडकरी ने मध्य प्रदेश में 11,427 करोड़ रुपये लागत की 45 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''एक लाख करोड़ रुपये की लागत से संभवत: दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर पूरा हो जायेगा।''

राज्य की इन 45 परियोजनाओं में से 26 पूरी हो चुकी हैं और 19 के लिये मंगलवार को शिलान्यास किया गया।

गडकरी ने कहा कि आठ लेन एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद दिल्ली और मुंबई की दूरी को 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसमें से 244 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरेगा।

उन्होंने प्रदेश सरकार से इस एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक और 'लॉजिस्टिक हब' विकसित करने की योजनाएं तैयार करने के लिये कहा। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये की लागत वाले 358 किलोमीटर लम्बे चंबल एक्सप्रेसवे की मंजूरी की भी घोषणा की। यह कोटा-श्योपुर-इटावा के जरिये मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जोड़ेगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.